REFERENCE TO THE PLIGHT OF VEHICLE OPERATORS IN RAJASTHAN AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY DUE TO MECHANICAL AND MANUFACTURING DEFECTS IN CANADA FORD TRUCKS MANUFACTURED IN MADRAS

श्री कंवर लाल पंवार (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा जो अत्यन्त आवश्यक जनहित से सम्बन्धित है आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन मालिक बनाने की आकर्षित योजना के तहत सिमसन कम्पनी मद्रास द्वारा विदेशी सहयोग से निर्मित "कनेडा फोर्ड ट्रक" भारत के बाजार में लाई गई थी। सन् 1980 में सैंकड़ों की तादाद में उक्त "कैनेडा फोर्ड ट्रक" का विक्रय, वाहन चालकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुलभ करा कर किया गया था।

कनाडा फोर्ड ट्रक का उत्पादन सम्पूर्ण दोषपूर्ण था। यह इस तथ्य से सिद्ध हो चुका है कि यह ट्रक रोड पर आते ही केवल तीन माह की अल्प अवधि में लगभग सभी ट्रक फेल हो गये। इस ट्रक की विक्रय कीमत दो लाख छब्बीस हजार रखी गई थी। टाटा ट्रक की कीमत से पचास हजार रुपये अधिक है। इतना ही नहीं इस ट्रक के स्पेअर पार्ट्स की कीमत अन्य ट्रकों के पार्ट्स की कीमत से दस गुना अधिक है और साथ ही अब बाजार में उपलब्ध भी नहीं है।

कैनेडा फोर्ड ट्रक की भार क्षमता कम होते हुए भी अधिक भार क्षमता होने की गलत तरीके से प्रमाणित करवाया। इस ट्रक के सड़क पर आते ही इंजिन डिफरेन्शियल एवं गेअर्स में खराबी आ गई। इंजिन ओवरहीट से फेल हो गये। डिफरेंशियल में प्रथम दिन से ही आवाज पैदा हो गई। गेअर्स में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वह इंजिन व डिफरेंशियल में सामन्जस्य पैदा कर सके। उपरोक्त खराबी के कारण एक्सल टूट गये और कैनेडा फोर्ड ट्रक बिल्कुल फेल हो गये हैं। इसके फलस्वरूप सैंकड़ों नवयुवकों एवं ड्राइवरों द्वारा किया हुआ नियोजन बिलकुल फेल हो गया।

बैंकों एवं वित्त निगमों से ली गई कर्ज की राशि का भुगतान करना दुर्लभ हो गया है और बैंकों ने कर्ज की राशि की वसूली के लिए सैंकड़ों मुकदमें दायर कर दिये हैं। बैंकों एवं वित्त निगमों द्वारा इस ट्रक पर ऋण देना बन्द कर दिया है एवं बीमा कम्पनियों ने भी उक्त ट्रकों का बीमा करना बन्द कर दिया है। एक ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों की करोड़ों रुपये की राशि ब्लाक हो गई है तो दूसरी ओर चालक जो वाहन मालिक बनने के स्वप्न संयोये हुए थे उनका सर्वस्व लुट गया है और दाने दाने के लिये मोहताज हो गये हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें जिन्होंने यह ट्रक खरीदे हैं वह भी भारी आर्थिक हानि की शिकार हुई हैं।

लगभग तीन लाख की कीमत के यह ट्रक सड़क के किनारे पत्थरों पर खड़े हैं जिनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट परिवहन विभाग में जमा करा दिये गये हैं। उनकी स्क्रैप की कीमत केवल तीस हजार ही रह गई है। इसलिए ऋण व ब्याज की बड़ी राशि चालकों व जमानतदारों के सिर पर नंगी तलवार की तरह से लटक रही है। राजस्थान में रहने वाले खरीददार अकाल से ग्रसित हैं और उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। उपरोक्त समस्या लोक महत्व की है और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि :—

(1) सिमसन कम्पनी मद्रास द्वारा निर्मित कैनेडा फोर्ड ट्रक के

खरीददारों के विरुद्ध बैंकों एवं वित्त निगमों द्वारा दायर किये गये वाद एवं वसूली की कार्यवाही तुरन्त प्रभाव से स्थगित कराई जावे एवं बैंकों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जायें ।

(2) सरकार द्वारा मध्यस्थता कर न्यायालय में चल रहे वादों का समुचित निर्णय कराया जावे ।

(3) गरीब चालकों, खरीददारों को अविलम्ब राहत पहुंचाई जावे एवं उनके विरुद्ध प्रारम्भ किये गये वाद अवैध घोषित किये जावें ।

महोदया, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा की इसी प्रकार का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हिन्दुस्तान ट्रक मिनी बस के संबंध में 17.3.86 को सदन में उठाया गया था परन्तु उसके संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं आज तक हमें कोई जानकारी नहीं दी गयी है अंतः आप सरकार को निर्देश देने का श्रम करेंगे कि हमें जानकारी देवें और साथ ही आज के इस प्रस्ताव के संबंध में भी तत्काल कदम उठाकर ड्राइवरों एवं वाहन मालिकों को राहत पहुंचायें । (धन्यवाद)

REFERENCE TO THE REPORTED GOVERNMENT DECISION TO CLOSE DOWN THREE UNITS OF THE HINDUSTAN FERTILISER CORPORATION LIMITED IN ASSAM

SHRI NAGEN SAIKIA (Assam): Madam, I am thankful to you for permitting me to raise the question of the fate of the HFCL factories.. The Central Government's move to close down three factories of the Hindustan Fertiliser Corporation Limited, briefly HFCL, in the eastern sector i. e. in Namrup, Barauni and Durgapur, is going to affect 10, 000 direct employees, a good number of contractors, which will cross a few thousand number, thousand's of families of the employees, labourers, huge number of daily wage-earners and petty contractors badly. Moreover, development for agriculture and agricultural production will be slowed down, ancillary industries like Assam Petro-Chemicals will be badly affected. The decision to stop the commissioning activities at Haldfa project and its associated offices also carries the indication of dark future of the project.

Assam, being one of the richest States in natural resources and the most backward in industrialisation in the country, has enough reasons to feel that the Central Government always has been trying to keep away the State from the industrial map of the country. For even a small industry, the people of the State are to launch agitational programmes, sometimes to lay even precious lives for such causes.

It is also found that most of the so-called expertise, of course not all, sent from other parts of the country, have least love for the State and least commitment for her development. They always try to build up their own images brightly at the cost of those industries or corporations and by showing inefficiency of the local people. I apprehend the existence of such -evil hands behind the decision of the Government to close down these factories on the plea that these factories are giving much loss. In case, of Namrup, they even are trying to show that the long Anam agitation was a cause of loss for the project. These people can only damage the cause of the State. Moreover, the main reasons for incurring loss are not spelled out by the authorities before the country. The first and the foremost reason is of using unproven indigenous technology for such big projects, while in other parts of the country proven technology has been and is being used for such projects. For example, Nangal and Bhatinda can be cited. But the factories of the HFCL are neglected and are denied of all facilities rendered to other factories. There is break down of unproven and obsolete equipment